बेदम चीनी मिलों से बिजली की आस

दैनिक जागरण P-13, 18/6/12

अवनीश त्यागी, लखनऊ

- विद्युत उत्पादन दो हजार मेगावाट करने के प्लान में निगम बाधक
- तकनीकी तौर पर पिछड़ी मिलों के आधुनिकीकरण की जरूरत

सूबे की चीनी मिलों में प्रदूषण मुक्त विद्युत (ग्रीन पॉवर) उत्पादन बढ़ाने की आस मिलों के मौजूदा हालत और उप्र बिजली निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के ढुलमुल रवैये के चलते पूरी होना आसान नहीं है।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मंशा है कि चीनी मिलों का विद्युत उत्पादन 829 से बढ़कर दो हजार मेगावाट हो ताकि बिजली संकट से राहत मिले और प्रदूषण रहित ऊर्जा की मुहिम को भी सफलता मिले। वैसे भी थर्मल प्लांटों के मुकाबले चीनी मिलों में बगास से तैयार बिजली पर लागत कम ही आती है। यूं तो प्रदेश में 123 चीनी मिलों में गन्ने की पेराई होती है, परंतु अतिरिक्त बिजली उत्पादन केवल 52 मिलें ही कर पा रही है। सहकारी क्षेत्र की 21 मिलों की मशीनें इतनी पुरानी है कि वो अपने प्रयोग की बिजली बामुश्किल उत्पादित करती है। इसी तरह निजी क्षेत्र की 71 मिलें भी अपने उपयोग भर को बिजली बनाती है।

सवाल यह है कि सस्ती बिजली तैयार करने की संभावनाएं होने पर भी मिलें अतिरिक्त विद्युत उत्पादन में दिलचस्पी क्यों नहीं लेती? चीनी उद्योग से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी इसके लिए **सरकार के उदासीन रवैये और अधिकांश मिलों में** आधुनिक मशीनें व तकनीक उपलब्ध न होने को जिम्मेदार मानते है। बढ़ती देनदारी के चलते मिलों का आधुनिकीकरण कराना सरल नहीं है।

विभागीय आंकड़ों के मुताबिक निजी और सहकारी चीनी मिलों पर किसानों के करीब 3064 करोड़ रुपये अवशेष है। जिसमें से निजी मिलों पर 2,521 करोड़ तथा सहकारी मिलों पर करीब 543 करोड़ रुपये बकाया है। सरकार ने 2011-12 पेराई सत्र के 3,000 करोड़ रुपये से अधिक एरियर भुगतान को नोटिस जारी किया है। इस साल में करीब 18,200 करोड़ रुपये भुगतान होना बाकी है। ऐसी आर्थिक स्थिति में चीनी मिलों को विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए नए टरबाइन व बायलर आदि खरीदना मुश्किल होगा। चीनी निर्यात का अपेक्षित लाभ प्रदेश की मिलों को नहीं मिल सका।

आड़े आता है बिजली विभाग का ढुलमुल रवैया : चीनी मिलों में बिजली का उत्पादन बढ़ाने में विद्युत विभाग का ढुलमुल रवैया भी आड़े आता है। जिन 52 मिलों द्वारा उप्र बिजली निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल) को विद्युत आपूर्ति की जा रही है, उन्हें अर्से से भुगतान नहीं मिल पाया। **लगभग 662 करोड़ रुपये की रकम यूपीपीसीएल** पर बकाया है। ग्रिड सिस्टम लचर होने का नुकसान भी विद्युत आपूर्तिकर्ता को झेलना पड़ता है। मिलों द्वारा बिजली सीधे स्टेट ग्रिड पर डालने से तकनीकी बाधाएं आती है। आए दिन होने वाले फाल्ट दूर करने की प्रभावी कार्ययोजना न होने का खामियाजा भी मिलों को ही भुगतना पड़ता है। आपूर्ति अनुबंध की प्रक्रिया सही नहीं होने और बिजली के रेट कर्नाटक जैसे प्रदेशों की तुलना में कम होने जैसी शिकायत भी है।

बगास की कमी और कोयले की जरूरत : मिलों के लिए जरूरत के मुताबिक बगास कम होना एक बड़ी समस्या है। पेराई सत्र के दौरान तो बगास उपलब्ध रहती है परन्तु मई - जून के बाद बायलर चलाने को पर्याप्त बगास नहीं मिलती। करीब चार महीने के लीन पीरियड में चीनी मिलों को बिजली उत्पादन करने के लिए कोयला चाहिए परन्तु सरकार खुद ही कोयले की किल्लत से परेशान है। 12 महीने बिजली आपूर्ति को बरकरार रखने के लिए केवल बगास पर निर्भर नहीं रहा जा सकता।

सरकार सहयोग करे: पटौदिया : यूपी इस्मा के चेयरमैन सीबी पटौदिया का कहना है कि कोजनरेशन से मिलों की दशा सुधरेगी, परंतु पहले सरकार का सकारात्मक सहयोग जरूरी है। बकाया भुगतान को सरकार सस्ती दर पर कर्ज मुहैया करा दे तो मिलों की आर्थिक स्थिति सुधर जाए। यूपीपीसीएल से अनुबंध शर्तों और बिजली भुगतान को सुव्यवस्थित करना होगा। कर्नाटक की तरह मिलों को उनकी बिजली का रेट मिलने लगे तो उत्पादन उम्मीद से भी अधिक हो सकेगा।